s. No.	Name of Scheme	Allocation Rs. in lakhs)	Release's	Expenditure	No. of benefited
1.	NOAPS	4403.70	4281.00	3679.37	514946
2.	NFBS	2269.58	1538.28	984.70	15383
3.	NMBS	1222.83	1065.78	658.81	188109

Information in respect of rural women of Monitory communities and backward classes is not being maintained separately.

मध्य प्रदेश में ग्रामीण आवासों की कमी के लिए सर्वेक्षण

2840.**श्री दिलीप सिंह जूदेव**: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में आवासों की कमी के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है या किये जाने का विचार हैं;

(ख) क्या पिछड़े क्षेत्रों और गरीब लोगों के क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त आवासीय इकाई हेतु जिला-वार मांग संबंधी कोई मूल्यांकन कियाग या हैं;

(ग) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मध्य प्रदेश सरकार राजगढ़,विदिशा,भोपाल और इन्दौर जिलों में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता से आवासों का निर्माण करवाने का विचार रखती है;और

(ड) यदि नहीं,तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा): (क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई सूचना के अनुसार ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया हैं/ कराने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़े क्षेत्रों और गरीब लोगों के क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त आवासीय इकाई हेतु क्षेत्रवार और जिला-वार मूल्यांकन नहीं किया गया हैं।

(ग) उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी,हां।

(ड़) उपरोक्त को देखते हुए,प्रश्न नहीं उठता।

जनजातीय भूमि के अधिग्रहण पर प्रतिबंध

2841. **श्री अजीत जोगी**:
श्री रामजीलाल:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को जनजातीय और फालतू भूमि के अधिग्रहण के लिए कानून लागू करने हेतु कोई निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या-क्या हैं जहां ऐसे कानून लागू नहीं किये गये हैं;

(घ) इन कानूनों के अंतर्गत प्रत्येक राज्यों में कुल कितनी एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है; और

(ड) सरकार द्वारा ऐसे कानूनों के लागू करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने की संभावना हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा): (क) मंत्रालय ने इस विषय में राज्य सरकार को कोई अनुदेश जारी नहीं किए है।

(ख)से (ड़) प्रश्न नहीं उठता।

Wasteland in Tamil Nadu

2842. SHRI V. RAJAN CHELL-APPA: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the total area of wasteland in Tamil Nadu;

(b) the steps taken by the Government to develop wasteland in the State for cultivation and other purposes;

(c) whether any amount has been aranted to the State Government or to